



इंदौर, मध्य प्रदेश सोमवार 14 सितंबर 2026, भाद्रपद शुक्ल - 2, अंक - 01, पृष्ठ - 8 , मूल्य - रु 2

खराखरा

18 करेट : ₹1,16,630
22 करेट : ₹1,42,550
24 करेट : ₹1,55,510

सकारात्मक सोमवारसर:

शुभ सोमवार की नई सुबह के साथ, सत्य और निडर पत्रकारिता के क्षितिज पर एक नए अध्याय का आरंभ हो रहा है। हमें आपके हाथों में 'देश दर्पण संवाद' का यह प्रथम अंक सौंपते हुए अपार हर्ष हो रहा है। हमारा मूलमंत्र— “हम खबर नहीं, आईना दिखाते हैं”— महज कुछ शब्द नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर आप तक पहुंचाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। आज के इस शुभ दिन से शुरू हो रही हमारी यह यात्रा, शोर-शराबे और सनसनी से दूर, केवल तथ्यों और ज़मीनी हकीकत पर आधारित होगी। आइए, सच को बिना किसी मिलावट के देखने के इस सफर में हमारे हमसफर बनें।

प्रथम पूज्य श्री गणेश के आशीर्वाद से ‘देश दर्पण संवाद’ का मंगल प्रवेश

विघ्नहर्ता के पावन पर्व पर सत्य, सरोकार और निष्पक्ष पत्रकारिता का नया अध्याय शुरू भोपाल। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के स्मरण से होती है। विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता गजानन नई शुरुआत, ज्ञान, और सकारात्मकता के प्रतीक हैं।

भावना और गणेशोत्सव के पावन पर्व के शुभ अवसर पर, 14 सितंबर को 'देश दर्पण संवाद' साप्ताहिक समाचार पत्र अपने पत्रकारीय सफर का श्रीगणेश कर रहा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह समाचार पत्र समाज, प्रदेश और राष्ट्र का एक सच्चा 'दर्पण' बनने के दृढ़ संकल्प के साथ आपके हाथों में है। आज के दौर में जब सूचनाओं की बाढ़ है, तब एक विश्वसनीय और बेबाक संवाद की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ जाती है। 'देश दर्पण संवाद' का उद्देश्य

देश दर्पण संवाद

हम खबर नहीं आईना दिखाते है

बिना किसी लाग-लपेट के, सत्य और सरोकार की पत्रकारिता को पाठकों तक पहुंचाना है। सत्ता के गलियारों की हलचल हो, विकास के नए आयाम हों, या आम आदमी के जीवन से जुड़े जमीनी मुद्दे—हर वह खबर जो जनता के लिए मायने रखती है, इस दर्पण में पूरी स्पष्टता के साथ दिखाई देगी। भगवान गणपति के आशीर्वाद से

शुरू हो रही इस यात्रा में हमारा ध्येय निर्भीक और जनहितैषी रहना है। पत्रकारिता के उच्च मापदंडों पर खरे उतरने के लिए इसमें हमें विवेक और शक्ति प्रदान करें, यही हमारी मंगलकामना है। सत्य को सामने लाने की 'देश दर्पण संवाद' की इस नई यात्रा में सुधी पाठकों का सहज, समर्थन और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा।



पत्रकारिता के उत्त्व मापदंडों पर खरे उतरने के लिए बप्पा हमें विवेक और शक्ति प्रदान करें, यही हमारी मंगलकामना है। सत्य को सामने लाने की 'देश दर्पण संवाद' की इस नई यात्रा में सुधी पाठकों का सहज, समर्थन और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा।

एक ही कार में सवार हुए मोदी-पुतिन, दुनिया को दिया गहरी दोस्ती का संदेश

कूटनीति का नया अध्याय



नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में 45 मिनट तक अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। इस मुलाकात की शुरुआत दोनों नेताओं के गर्मजोशी से गले मिलने के साथ हुई। हालांकि, इस पूरी मुलाकात में जिस बात ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक जानकारों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वह था दोनों नेताओं का एक ही कार में बैठकर इंस्टिट्यूट एजीबिशन (औद्योगिक प्रदर्शनी) तक पहुंचना। एक ही कार में सफर के क्या हैं कूटनीतिक मायने? अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में 'प्रोटोकॉल' और 'बॉडी लैंग्वेज' का बहुत महत्व होता है। जब दो बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपना-अपना सुरक्षा घेरा और अलग काफिला छोड़कर एक ही कार में सफर करते हैं, तो इसके कई गहरे अर्थ होते हैं:

अटूट विश्वास और व्यक्तिगत तालमेल: एक ही कार में साथ सफर करना मोदी और पुतिन के बीच मजबूत व्यक्तिगत केमिस्ट्री और दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे को दर्शाता है। यह साबित करता है कि भारत और रूस के रिश्ते महज औपचारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और भावनात्मक स्तर पर भी बेहद मजबूत हैं।

पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश: मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में, जब रूस पर कई तरह के दबाव हैं, तब भारतीय प्रधानमंत्री का रूसी राष्ट्रपति के साथ इतना सहज और आत्मीय दिखना दुनिया (विशेषकर पश्चिमी देशों) को यह स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है और रूस उसका सदाबहार मित्र बना रहेगा।

अनौपचारिक बातचीत का अवसर: एक कार में बिना किसी बड़े प्रतिनिधिमंडल के सफर करने से दोनों नेताओं को कुछ बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे और एकांत में बात करने का अवसर मिलता है।

वैश्विक तनाव और शांति पर भारत का स्पष्ट रुख इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत-रूस के द्विपक्षीय रिश्तों के साथ-साथ मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) और ब्लैक सी (काला सागर) में जारी मौजूदा तनाव पर भी गंभीर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत का रुख एक बार फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी विवाद या संघर्ष का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को आश्चस्त किया कि भारत विश्व में शांति बहाल करने की कोशिशों में हरसंभव मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सांस्कृतिक कूटनीति और अगामी दौरा बैठक के दौरान सांस्कृतिक संबंधों को भी तरजीह दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को प्राचीन तमिल ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' की रूसी भाषा में अनुवादित एक प्रति सप्रेम भेंट की।

वार्ता के दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को 24वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ताओं का यह सिलसिला भविष्य में भी इसी मजबूती के साथ जारी रहेगा।

हिंदी दिवस विशेष

1900 की ‘इंद्रमती’ से लेकर वैश्विक पटल तक आधुनिक हिंदी का सफर

हिंदी दिवस विशेष: ‘देश दर्पण संवाद’ के पहले संस्करण के शुभारंभ पर हिंदी दिवस विशेष

इंदौर । आज 14 सितंबर को पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। 'देश दर्पण संवाद' के प्रथम संस्करण के शुभारंभ के लिए इससे अधिक गौरवमयी अवसर और क्या हो सकता है। आज हम जिस हिंदी को आसानी से लिखते और बोलते हैं, उसकी शुरुआत मुख्य रूप से वर्ष 1900 में हुई थी। इसी वर्ष किशोरीलाल गोस्वामी ने 'इंद्रमती' नामक कहानी लिखी थी, जो पूरी तरह से हिंदी खड़ी बोली और गद्य अंदाज में रची गई पहली रचना थी। इसकी भाषा एकदम वैसी ही थी, जैसी आज लिखी-बोली जाती है।

साहित्यिक भाषा से निकालकर आम बोलचाल और जनमानस की भाषा बनाने में काशी के साहित्यकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है।

यह वही धरती है जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक साहित्यिक हिंदी की नींव मजबूत की। काशी के प्रमुख आधुनिक हिंदी के जन्मदाताओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ-साथ मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह जैसे युगप्रवर्तक शामिल हैं।

अकादमिक मंच पर हिंदी को स्थापित करने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय

काशी हिंदू विश्वविद्यालय का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ही वर्ष 1900 में कचहरियों में देवनागरी लिपि को स्वीकार्यता मिली थी। बीएचयू के हिंदी विभाग के प्रोफेसर श्रीप्रकाश शुक्ल के अनुसार, बीएचयू देश का पहला विभाग था जिसने हिंदी की पूरी और व्यवस्थित पढ़ाई शुरू की। वर्ष 1919 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को यहां हिंदी का प्रोफेसर बनाया गया।

इसके ठीक बाद 1920 में बीएचयू में हिंदी की पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) की पढ़ाई शुरू हुई। 1937 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बीएचयू के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। आज 'देश दर्पण संवाद' के अखबार के माध्यम से हम हिंदी पत्रकारिता और भाषा के इन्हीं महान आदर्शों, समृद्ध परंपराओं और साहित्यकारों के योगदान को नमन करते हैं। आप सभी पाठकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

हिंदी का यह सफर इतना आसान नहीं रहा। 1904 ईस्वी में उत्तर भारत के हर स्कूल में इस भाषा को पढ़ाए जाने की मांग उठी। इसके जवाब में 1905 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के खिलाफ एक सूचना निकाली और कहा कि यह मुल्क की सरकार और दफ्तरी जुबान नहीं है। लेकिन भाषा का विकास रुका नहीं।

1909 में 'पुष्पाटिका' और 1913 व 1915 में इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल की किताबों के अनुवाद और लेखन ने खड़ी बोली को स्थापित किया। अंततः 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा में आज़ाद भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। आज हिंदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। 2011 के एक सर्वे के दावे के अनुसार, दुनिया की 18% आबादी हिंदी समझती है, जो कि चीनी भाषा मेंडरिन (15.27%) और अंग्रेजी (13.85%) को समझने वालों से भी अधिक है।

काशी और बीएचयू का ऐतिहासिक योगदान

जब भी हिंदी की समृद्ध परंपरा की चर्चा होती है, तो काशी का नाम प्रमुखता से आता है। हिंदी को कठिन

भारत की जीडीपी विकास दर 7.8% दर्ज



दिल्ली । भारत की यह शानदार आर्थिक वृद्धि ऐसे समय में सामने आई है जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी, महंगाई और सुस्ती के दौर से गुज़र रही हैं। 7.8% की इस मजबूत ग्रोथ ने साबित कर दिया है कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली और तेजी से आगे बढ़ने वाली है। इस शानदार ग्रोथ के मुख्य कारण और प्रभाव: उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन: वित्तीय विश्लेषकों ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान इससे कम लगाया था, लेकिन विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग),

कृषि और सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) में आए उछाल ने इन सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया। मजबूत घरेलू मांग: वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनावों और अस्थिरता के बावजूद, भारत के भीतर घरेलू खपत, निवेश और मांग का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है, जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहारा: IMF की टिप्पणी यह स्पष्ट करती है कि 7.8% की इस उच्च विकास दर के साथ भारत अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने और उसे आगे बढाने में एक ड्राइविंग फोर्स की भूमिका निभा रहा है। निवेशकों का भरोसा: अनुमान से अधिक जीडीपी ग्रोथ विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को यह साफ संदेश देती है कि भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे सुरक्षित और आकर्षक निवेश बाजार है। यह आंकड़ा केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि इस बात की मुहर है कि भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अपने तय लक्ष्यों से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सरकार झुकी, स्टाइपेंड बढ़ा: 52 घंटे के गतिरोध के बाद इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल खत्म

डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद काम पर लौटे डॉक्टर, वजीफा 14,337 से बढ़कर हुआ 21,500 रुपये। वाटर कैनन विवाद में एएसआई और सिपाही लाइन अटैच, आईएएस शिल्पा गुप्ता को सौंपी गई जांच।

● प्रकाश त्रिपाठी, शिवम शुक्ला

भोपाल। राजधानी भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों का 52 घंटे लंबा आंदोलन सरकार के सीधे दखल के बाद अंततः समाप्त हो गया है। लगभग दो महीने से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे इन डॉक्टरों के समर्थन में जूनियर डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट्स के भी उतर आने से हमीदिया अस्पताल की ओपीडी और ऑपरेशन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई थीं। वहीं, कमला पार्क और आसपास के इलाकों में सड़क पर उतरे डॉक्टरों के कारण शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। इस भारी गतिरोध को तोड़ने के लिए उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वयं जीएमसी (गांधी मेडिकल कॉलेज) पहुंचकर छात्र प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस निर्णायक वार्ता के बाद सरकार ने इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा कर दी। अब प्रदेश के इंटर्न डॉक्टरों को 14,337 रुपये की जगह 21,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, हालांकि छात्रों की मूल मांग 30 हजार रुपये की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखने वाले छात्रों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और पुलिस बल प्रयोग

में घायल छात्रों के समुचित उपचार की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार के इस फैसले के बाद डॉक्टरों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं फिर से संचारु हो गई हैं। वाटर कैनन विवाद: जांच के आदेश, निचले स्तर पर गिरी गाज बीते 7 सितंबर के प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों पर अब प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है। गृह विभाग ने आईएएस शिल्पा गुप्ता (सचिव) को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, जो एक सप्ताह के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले में फौरी कार्रवाई के नाम पर एसीपी कार्यालय हनुमानगंज में पदस्थ एएसआई नरेंद्र सिंह यादव और वाटर कैनन पुलिस कंट्रोल रूम के आरक्षक कृष्ण दत्त शिवहरे को लाइन अटैच कर दिया गया है। देश दर्पण का विशेष विश्लेषण: बड़े अधिकारियों की जवाबदेही कब? जीएमसी के छात्रों पर वाटर कैनन चलाने के मामले में पुलिस ने फुटेज के आधार पर एएसआई और आरक्षक पर तो तुरंत कार्रवाई कर दी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल अनंतरित है कि— वाटर कैनन चलाने का आदेश आखिर किसने दिया?



पुलिस मैज्युअल के मुताबिक, भीड़ पर बल प्रयोग का फैसला मौके पर मौजूद सभम अधिकारी के आदेश पर ही होता है। घटना के समय मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान, डीसीपी जोन-3 आयुष गुप्ता, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और टीआई समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। डीसीपी गुप्ता का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी, इसलिए वाटर कैनन चलाया गया। यहाँ प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: यदि वाटर कैनन चलाने का फैसला वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर हुआ, तो जवाबदेही तय कर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखना यह है कि प्रशासनिक जांच में इन बड़े सवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं।

एमपी नगर प्रेस कॉम्प्लेक्स में गूंजे नारे, बैंक यूनियनों ने दी चेतावनी- मांगें नहीं मानीं तो और तेज होगा आंदोलन

भोपाल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर देशभर में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रभावी हड़ताल की। “5-दिवसीय बैंकिंग लागू करो” और “बैंककर्मियों के स्वास्थ्य व सम्मान से समझौता नहीं” जैसे नारों के साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु सहित तमाम बड़े महानगरों व जिला मुख्यालयों पर बैंककर्मियों ने एकजुट होकर सरकार और बैंक प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस देशव्यापी हड़ताल का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी व्यापक असर देखने को मिला। भोपाल में हड़ताल का प्रमुख केंद्र एमपी नगर स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स (पीएनबी के पास) रहा। यहाँ 5000 से अधिक बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विशाल और शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि बैंक प्रबंधन और सरकार की टालमटोल की नीति अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने किया नेतृत्व भोपाल में इस विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व UFBU के संयोजक श्री संजीव कुमार मिश्रा, मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुबीन सिन्हा, सचिव दिनेश झा और भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ (भोपाल सर्कल) के अध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव ने किया। इनके साथ घटक दलों के वरिष्ठ कामरेड वीरू शर्मा, दीपकरत्न शर्मा, संजय कुदेशिया, नजीर कुशेशी, शोभित वादेल, प्रवीण मेघानी, वी.एस. नेगी, सुनील सिंह और संगठन के मीडिया प्रभारी अरविंद पंडियार ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। ‘5-दिवसीय बैंकिंग केवल सुविधा नहीं, बल्कि अनिवार्य सुधार’ धरने को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 5-दिवसीय बैंकिंग केवल कर्मचारियों की सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि यह बेहतर ग्राहक सेवा, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और



एक स्वस्थ कार्य-संस्कृति के लिए बेहद जरूरी सुधार है। नेताओं ने सरकार से मांग की है कि वह जमीनी हकीकत को समझे और लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय ले। यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। UFBU द्वारा भविष्य के लिए दिए गए सभी कॉल और विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा यथावत लागू रहेगी। बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी इस प्रदर्शन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से AIBOC के बैनर तले बैंककर्मियों ने हिस्सा लिया। हड़ताल में रजनीश पौराणिक, सुरेश बाबू मीणा, स्वप्निल चतुर्वेदी, क्षितिज तिवारी, मनीष भार्गव सहित बड़ी संख्या में युवा और महिला बैंककर्मियों (प्रियंका गुप्ता, सुखमीत कोर, मोनिका भागवानी, विनीता दुबे, पूजा कुशवाहा आदि) ने भी बहु-चड़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराई और आंदोलन को मजबूती दी।

पर्यावरण

मप्र को नई सौगात: 25 सितंबर से शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’



भोपाल। मप्र को नई सौगात: 25 सितंबर से शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ 2030 तक प्रदेश के 75% गांवों तक बसें पहुँचाने का लक्ष्य ‘रैपिडो’ (Rapido) के साथ एमओयू, ‘रैपिडो पिक’ से बढ़ेगा महिला सशक्तिकरण देश का ‘फाइनस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल’ बनेगा मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। दशकों से बंद पड़ी राज्य परिवहन बस सेवा की जगह अब एक नई, आधुनिक और सुरक्षित प्रणाली लेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित दो दिवसीय ‘यात्री परिवहन विजन समिट-2026’ का शुभारंभ करते हुए घोषणा की है कि आगामी 25 सितंबर से प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा’ का मंगल आरंभ किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2030 के अंत तक राज्य के 75 प्रतिशत गांवों को इस बस सेवा से जोड़ना है। ‘देश का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मॉडल बनाने की तैयारी’ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में बस ऑपरेटर्स, निर्माता कंपनियों और निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में 5 लाख किलोमीटर का शानदार रोड नेटवर्क है, जहां 15 हजार से अधिक बसें चलाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से सरकार के साथ जुड़कर राज्य में देश का ‘फाइनस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल’ तैयार करने की अपील की। यह

नई बस सेवा पूरी तरह से आधुनिक, सुरक्षित, ग्रीन और डिजिटल मोबिलिटी पर आधारित होगी। लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: MPYPIL और रैपिडो के बीच करार यात्रियों को उनके घर से बस स्टैंड तक (फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) सुलभ यातायात देने के लिए राज्य सरकार की संस्था MPYPIL और ‘रैपिडो’ (Rapido) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) साइन किया गया। पायलट प्रोजेक्ट: शुरुआत में यह सेवा भोपाल और इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगी। महिला सशक्तिकरण: महिलाओं द्वारा संचालित ‘रैपिडो पिक’ बाइक-टैक्सी सेवा को विशेष बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पर्यटन और रोजगार को मिलेगी संजीवनी मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ा है। पहले जहां उज्जैन में 60-70 लाख श्रद्धालु आते थे, वहीं अब यह संख्या 8 करोड़ पार कर गई है और इस साल 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। पूरे राज्य में हर साल 20 करोड़ से अधिक पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में ‘एक राज्य-एक बस सेवा’ न केवल यात्रियों की राह आसान करेगी, बल्कि प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार भी देगी।

पूर्व सांसद अशोक अर्गल मध्य प्रदेश ‘भारत स्काउट्स एवं गाइड्स’ के राज्य मुख्य आयुक्त निर्विरोध निर्वाचित

भोपाल। मुरैना और भिंड से पांच बार सांसद रहे तथा मुरैना के प्रथम महापौर अशोक अर्गल को मध्य प्रदेश ‘भारत स्काउट्स एवं गाइड्स’ का पुनः राज्य मुख्य आयुक्त चुना गया है। 2026 की चुनाव प्रक्रिया में वे इस पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद, राज्य मुख्य आयुक्त पद के लिए अर्गल ही एकमात्र वैध प्रत्याशी बचे थे। कोई अन्य उम्मीदवार न होने के कारण इस पद के लिए 23 सितंबर 2026 को प्रस्तावित मतदान की आवश्यकता नहीं रही और उन्हें निर्विरोध विजेता मान

लिया गया। हालांकि, संगठन में पुरुष उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए 23 सितंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही मतदान होगा। अशोक अर्गल के लंबे राजनीतिक और सामाजिक अनुभव को देखते हुए, उनके पुनः इस पद पर काबिज होने से प्रदेश में स्काउट-गाइड की गतिविधियों को नई दिशा और प्रशासनिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

युवाओं की आवाज उठाने इंदौर आ रहे हैं राहुल गांधी

इंदौर। ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के जरिए शिक्षा, भर्ती और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी देश दर्पण संवाद ब्यूरो/ इंदौर। देश की आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र इंदौर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं, प्रतियोगी छात्रों और शोधार्थियों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आगामी 19 सितंबर को इंदौर के दौरे पर आ रहे हैं। उनके बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज’ को लेकर प्रशासनिक गलियारों में बीते कई दिनों से बना सस्पेंस आखिरकार समाप्त हो गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) ने तमाम औपचारिकताओं के बाद 11 सितंबर को रीजनल पार्क के सामने स्थित आईडीए ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित करने की आधिकारिक अनुमति जारी कर दी है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 10 लाख 8 हजार 175 रुपये की निर्धारित राशि भी प्राधिकरण में जमा कर दी है। **तीन दिवसीय आयोजन: संवाद से लेकर सांस्कृतिक ऊर्जा का समागम** प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह समग्र आयोजन 17 से 19 सितंबर तक चलेगा, जिसके अंतिम दिन यानी 19 सितंबर को राहुल गांधी सीधे छात्रों से रुबरु होंगे। कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पारंपरिक राजनीतिक सभाओं से बिल्कुल जुदा रखी है। संवाद सत्र की शुरुआत से पहले युवाओं की रुचि और ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रखी गई हैं: राघव चैतन्य: बॉलीवुड के चर्चित पार्श्व गायक और फिल्मफेयर पुरस्कार विजेता राघव चैतन्य अपने



लोकप्रिय गीतों से समां बांधेंगे। लश-करी: मालवा और इंदौर के युवाओं में खासे लोकप्रिय रैपर लश-करी अपनी तेजतर्रार बीट्स और सामयिक विषयों पर आधारित गानों से माहौल में जोश भरेंगे।कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 11 सितंबर को दिल्ली से राहुल गांधी की कोर टीम के प्रमुख सदस्य के.वी. बैजू सहित अन्य वरिष्ठ रणनीतिकार इंदौर पहुंचे थे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक हुई। बैठक में न

सिर्फ इंदौर शहर, बल्कि आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों और संभाग के अन्य जिलों से भी छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का खाका तैयार किया गया। **जमीनी स्तर पर लामबंदी: 32 जोंनों में बंटा शहर** कार्यक्रम में केवल भाषणबाजी न हो, बल्कि वास्तविक मुद्दों पर मंथन हो, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) और युवा कांग्रेस ने व्यापक अभियान छेड़ दिया है:

1. 32 जोंनों में विभाजन: पूरे इंदौर महानगर को 32

जोंनों में बांटकर प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।

2. संस्थानों तक सीधी पहुंच: एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर के प्रमुख हॉस्टलों, निजी व सरकारी लाइब्रेरी, कॉरिंग संस्थानों और कॉलेज परिसरों में संपर्क कर रहे हैं।

3. मुद्दों का संकलन: छात्रों से सीधे संवाद कर यह जाना जा रहा है कि वे व्यवस्था में क्या बदलाव चाहते हैं, ताकि 19 सितंबर के मंच पर वही सवाल सीधे तौर पर गूंज सकें। जीतू पटवारी का तीखा हमला: ‘शिक्षा और रोजगार की टूटती कड़ी सबसे बड़ा संकट’ रविवार को इंदौर में आयोजित विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में शिक्षा और रोजगार के बीच का तालमेल पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। माता-पिता लाखों रुपये खर्च कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिग्री पूरी होने के बाद उनके हाथ खाली हैं। पटवारी ने हालिया NEET पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षाओं में सामने आई विसंगतियों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी अनियमितताओं ने देश के लाखों मेधावी छात्रों के सपनों पर पानी फेर दिया है। अगर सरकार व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में नाकाम रही है, तो उसे देश के नौजवानों के सामने इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सस्ती शिक्षा (अफोर्डेबल एजुकेशन) और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया आज के समय की

सबसे अनिवार्य मांग है, और राहुल गांधी इसी राष्ट्रीय विमर्श को जमीन पर ले जाने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक मायने: युवाओं के सहारे ‘मिशन 2027’ की रूपरेखा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का यह दौरा महज एक रूटीन संवाद नहीं, बल्कि दूरगामी सियासी रणनीति का हिस्सा है: सीधी राजनीतिक पैर: युवाओं और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत करना। भर्ती और बेरोजगारी को केंद्रीय मुद्दा बनाना: स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बेरोजगारी और पेपर लीक के मामलों को प्रमुख राजनीतिक विमर्श में तब्दील करना। सड़क से सदन तक लड़ाई: भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्रों की समस्याओं को एक संगठित मंच प्रदान कर सीधा मुकाबला खड़ा करना। बड़ा शक्ति प्रदर्शन: पूर्व में किसी कारणवश स्थगित हुए कार्यक्रमों के बाद यह दौरा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा अवसर बन गया है। राहुल गांधी के शब्दों में, “भारत की शिक्षा व्यवस्था उस युवा पीढ़ी को निराश कर रही है, जिसके कंधों पर देश का भविष्य है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की शुरुआत केवल उन छात्रों की बात सुनकर ही हो सकती है, जो रोज इसकी कमियों का सामना कर रहे हैं।” अब देखना यह होगा कि 19 सितंबर को रीजनल पार्क में मैदान से उठने वाली ‘छात्रों की गूंज’ सत्ता के गलियारों में कितनी दूर तक असर छोड़ती है।

आत्मनिर्भर भारत

रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ का महा-शंखनाद

₹1.10 लाख करोड़ के स्वदेशी सैन्य सौदों को ऐतिहासिक मंजूरी रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) का युगांतरकारी फैसला; स्वीकृत प्रस्तावों का 98% हिस्सा घरेलू उद्योगों से खरीदा जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा—”यह नए और सशक्त भारत की सैन्य शक्ति का उदय है।”

नई दिल्ली

भारत ने रक्षा उत्पादन और सैन्य आधुनिकीकरण के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की उच्च स्तरीय बैठक में तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को अभेद्य बनाने के लिए ₹1,10,000 करोड़ के पुंजीगत खरीद प्रस्तावों को ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (AoN) दे दी गई है। भू-राजनीतिक तनाव और सीमाओं पर उभरती नई चुनौतियों के बीच लिया गया यह फैसला भारतीय सैन्य इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। इस महा-सौदे की सबसे युगांतरकारी विशेषता यह है कि कुल स्वीकृत राशि का 98 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी उद्योगों (IODM श्रेणी) से ही अधिप्राप्त किया जाएगा, जो ‘मेक इन इंडिया’ संकल्प को धरातल पर उतारता है।

थल सेना: अभेद्य सुरक्षा कवच और ‘CBRN’ टोही वाहनों से लैस होंगे जांबाज

उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर समकालीन सुरक्षा परिदृश्यों और संभावित खतरों को देखते हुए भारतीय थल सेना को अत्यधिक आधुनिक और आक्रामक तकनीकी से लैस किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सेना के लिए विशेष रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) टोही वाहनों की खरीद को हरी झंडी दी गई है। ये वाहन युद्ध क्षेत्र में किसी भी

घातक या दूषित वातावरण की सटीक पहचान करने में सक्षम होंगे।

इसके साथ ही:

- * दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में त्वरित तैनाती के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स (HMMV)।
- * दुश्मन की घेराबंदी और बारूदी सुरंगों को ध्वस्त करने के लिए अत्याधुनिक ट्रॉल टैंक।
- * सेना के निर्बाध मूवमेंट के लिए स्वदेशी सर्वत्र ब्रिज सिस्टम।
- * अचूक मारक क्षमता के लिए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव की नई खेप को बेड़े में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।

नौसेना और वायुसेना: हिंद महासागर में बढ़ेगी धक, आसमान में अचूक होगी मार रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारतीय नौसेना की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। नौसेना के युद्धपोतों के लिए स्वदेशी मरीन गैस टर्बाइन (MGT) के डिजाइन और विकास को स्वीकृति दी गई है, जो भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके अलावा, समुद्र और तटीय सीमाओं की अचूक निगरानी के लिए अत्याधुनिक ‘अरुणा रडार’ प्रणालियों की तैनाती की जाएगी।

वहीं, भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों की

मारक क्षमता को कई गुना



उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और महत्वपूर्ण अपग्रेड प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

कूटनीतिक मोर्चे पर भी बड़ी कामयाबी: श्रीलंका से रक्षा समझौते और S-400 पर रूस का बड़ा आश्वासन इस सप्ताह भारत ने न केवल अपनी आंतरिक ताकत बढ़ाई, बल्कि रक्षा कूटनीति के पटल पर भी बड़े संदेश दिए:

1. कोलंबो में भारत की धमक: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की श्रीलंका की तीन दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तीन महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत भारत, श्रीलंकाई सेना को आधुनिक L70 विमान भेदी बंदूकें (Air Defence Guns) और उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे चीन की रणनीतिक घेराबंदी को तोड़ा जा सकेगा।
2. समय पर मिलेगी S-400 मिसाइल प्रणाली: वैश्विक प्रतिबंधों और तनाव के बीच, रूस की शीर्ष रक्षा एजेंसी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने कल (13 सितंबर) आधिकारिक रूप से आश्वासन दिया है

कि भारत को S-400 ट्राइफ मिसाइल रेंजिमेंट की अंतिम डिलीवरी वर्ष 2026 की तय समय-सीमा के भीतर ही पूरी कर दी जाएगी।

3. वियतनाम के साथ साझा रणनीति: आज नई दिल्ली में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप-मंत्री के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और चीन के बढ़ते दखल के खिलाफ एक मजबूत साझा रोडमैप तैयार किया गया।

संपादकीय दृष्टिकोण: आयात पर निर्भरता से ‘ग्लोबल डिफेंस हब’ बनने की ओर अग्रसर भारत रक्षा विशेषज्ञों और सैन्य विश्लेषकों के अनुसार, मात्र एक सप्ताह के भीतर ₹1.10 लाख करोड़ के स्वदेशी प्रस्तावों पर मुहर लगाना और पड़ोसी देशों के साथ रक्षा सहयोग को नया आयाम देना यह साफ करता है कि भारत अब केवल एक खरीदार देश नहीं रह गया है। भारत तेजी से एक निर्यातक और वैश्विक ‘डिफेंस हब’ बनने की दिशा में बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय का यह कदम भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र (MSMEs और निजी उद्योगों) के लिए एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत है।

देश में निवेश

मध्य प्रदेश में बड़े विदेशी निवेश की तैयारी

सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शरजाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स से की एहम मुलाकात फूड प्रोसेसिंग , लोजिस्टिक और रेनेवाबले एनर्जी सहित कई सेक्टर में नेवेश में बनी सहमति; ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 का दिया न्योता ।

भोपाल । मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और राज्य के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दौरे के सार्थक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। बीते कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को निवेश के अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, और मुख्यमंत्री का यह यूएई दौरा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपनी यात्रा के दौरान शारजाह चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन से एक महत्वपूर्ण और सारगर्भित मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग की संभावनाओं पर खुलकर विचार साझा किए। इस उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश और शारजाह के बीच आर्थिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने पर गहन विचार-विमर्श किया गया, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आने की प्रबल संभावनाएं बन गई हैं। बैठक में शामिल अधिकारियों के अनुसार यह वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और दोनों पक्षों ने भविष्य में नियमित संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई।

इन प्रमुख क्षेत्रों में निवेश पर हुआ मंथन

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शारजाह के उद्योगपतियों और निवेशकों को मध्य प्रदेश में मौजूद अनुकूल औद्योगिक माहौल, प्रचुर संसाधनों और अपार व्यावसायिक संभावनाओं से विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य के पास कुशल श्रमशक्ति, बेहतर कनेक्टिविटी और

सक्रिय नीतिगत समर्थन जैसे कई अनुकूल कारक मौजूद हैं, जो इसे निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद स्थान बनाते हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण), लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल (कपड़ा उद्योग), फार्मास्यूटिकल्स (दवा उद्योग) और रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर भी सहयोग की संभावनाएं तलाशी गईं। डॉ. यादव ने आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश सरकार ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत निवेशकों को हर संभव बुनियादी ढांचा, सब्सिडी और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अड़चन का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों में लगातार सुधार कर रही है।

ग्लोबल इन्वेस्टरस समिट (GIS) 2027 के लिए किया आमंत्रित

मध्य प्रदेश को एक प्रमुख ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के अपने विजन के अनुरूप, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शारजाह के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को राज्य में आयोजित होने वाले आगामी ‘ग्लोबल इन्वेस्टरस समिट’ (GIS) 2027 के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह समिट शारजाह के निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश के तेजी से बढ़ते बाजार को



करीब से समझने और यहां अपनी व्यावसायिक इकाइयों स्थापित करने का एक बेहतरीन मंच साबित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समिट में देश-विदेश के अनेक उद्योगपति, नीति-निर्माता और निवेशक हिस्सा लेंगे, जिससे मध्य प्रदेश को वैश्विक मंच पर अपनी औद्योगिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल ने भी इस आमंत्रण का स्वागत करते हुए समिट में सक्रिय भागीदारी की इच्छा जताई।

दौरे से प्रदेश के औद्योगिक विकास को मिलेगी नई दिशा

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह विदेशी दौरा राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की एक बड़ी रणनीतिक पहल माना

जा रहा है। शारजाह चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ हुई इस सकारात्मक और परिणाममूलक वार्ता से यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश और यूएई के बीच व्यापारिक संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की उच्च स्तरीय भागीदारी से न केवल विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, बल्कि राज्य में तकनीकी हस्तांतरण और कुशल प्रशिक्षण के भी नए रास्ते खुलेंगे। इससे न केवल प्रदेश में बड़ा पूंजी निवेश आएगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हज़ारों नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार का मानना है कि आने वाले महीनों में इस दौरे के ठोस परिणाम विभिन्न निवेश समझौतों और परियोजनाओं के रूप में सामने आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की सूची में और मजबूती से शामिल हो सकेगा।

भारतीय हिंदी समाचार पत्रों



● मयंक आनंद

झींकपानी, झारखंड । झींकपानी, झारखंड में सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से एक युग का अंत

पश्चिमी सिंहभूम (झारखंड): लगभग आठ दशकों तक झींकपानी की फैक्ट्री का सायरन आसपास के गांवों को बताता था कि कब उठना है, कब खाना है, और अंधेरा होने से पहले बच्चों को स्कूल से घर पहुंच जाना चाहिए।

बस के समय और चाय की दुकानें भी इसी सायरन के हिसाब से तय होते थे। पीढ़ियों से परिवार एक ही गेट के भीतर काम करते आए, और गेट के बाहर के स जी विक्रेता, दर्जी, रिक्शा चालक भी इसी की छाया में अपना जीवन बनाते रहे। 16 अगस्त 2026 को यह सीटी हमेशा के लिए स्वामोश हो गई। अडानी समूह द्वारा अधिग्रहण के चार साल बाद, अडानी-एसीसी चार्डबासा सीमेंट वर्क्स—देश के सबसे पुराने लगातार संचालित सीमेंट संयंत्रों में से एक—स्थायी रूप से बंद हो गया।

कंपनी के अनुसार संयंत्र निम्न कारणों से बंद हुआ: चूना पत्थर के भंडार समाप्त हो गए थे; दूर स्थित इकाइयों से क्लिंकर मंगाना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो गया था; और पुरानी मशीनरी नई, अधिक कुशल इकाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी।

स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

बड़े नियोक्ताओं की कमी वाले इस क्षेत्र में बंदी का दैनिक जीवन पर गहरा असर पड़ा है। स जी विक्रेता रुक्मिणी देवी ने बताया कि मई में परिचालन बंद होने के बाद से इलाका सुनसान हो गया है और उनका माल अब हफ्तों तक बिक नहीं पाता। लगभग 900 इकाइयों वाला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स काफी हद तक खाली पड़ा है। स जी विक्रेता दिलीप कर्मोदर के अनुसार बिक्री पहले प्रतिदिन 15,000-20,000 रुपये तक पहुंचती थी, जो अब घटकर 2,000-3,000 रुपये रह गई है। कंपनी संचालित एसीसी अस्पताल, जो चौबीसों घंटे चिकित्सा सेवाएं देता था, भी बंद हो चुका है। साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाले किरण सुंडी और परचून दुकान चलाने वाली गीता गोपे ने बताया कि नौकरियों की अनिश्चितता ने ग्राहकों की संख्या और आमदनी दोनों घटा दी है।

आय समाप्त होने के साथ कुछ महिलाएं फिर से दिहाड़ी मजदूरी या घरेलू काम की तलाश में हैं। यूनियन प्रतिनिधियों ने चिंता जताई कि आर्थिक तंगी के चलते परिवार बच्चों को स्कूल से हटा सकते हैं या पलायन के दौरान साथ ले जा सकते हैं—ग्यारह वर्षीय गुजन हेरसा अब अपने माता-पिता के साथ दिहाड़ी मजदूरी पर जाती है।

व्यापक संदर्भ: भारत में

औद्योगिक रोजगार

यह बंदी ऐसे समय आई है जब भारत के जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 2026 में लगभग 15-17% रहा—25% के नीतिगत लक्ष्य से काफी कम। भारत की लगभग आधी कार्यबल अब भी कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान पांचवें हिस्से से भी कम है। कुछ अर्थशास्त्री इसे “समयपूर्व निऔद्योगीकरण” कहते हैं, जहां विनिर्माण रोजगार निचले आय स्तर पर ही स्थिर या कम होने लगता है। झींकपानी को मुंबई की कपड़ा मिलों, कानपुर की औद्योगिक इकाइयों, उत्तरपाड़ा में हिंदुस्तान मोटर्स और अलीगढ़ के ताला उद्योग जैसे व्यापक पैटर्न का हिस्सा बताया गया है।

संयंत्र की पृष्ठभूमि

एसीसी की स्थापना 1936 में 11 छोटी सीमेंट कंपनियों के विलय से हुई थी, और 1940 के दशक में इसने भारत का पहला स्वदेशी सीमेंट संयंत्र बनाया। पश्चिमी सिंहभूम की पहाड़ियों में मिले चूना पत्थर पर आधारित इस संयंत्र ने परिवहनकर्ताओं, ठेकेदारों की एक सहायक अर्थव्यवस्था और एक अस्पताल व स्कूल को जन्म दिया, जो आज भी चल रहा है।

स्वामित्व दशकों में कई बार बदला—टाटा से गुजरात अंबुजा सीमेंट्स तक, और 2022 में अडानी समूह ने होल्सिम की एसीसी हिस्सेदारी करीब 10.5 अरब डॉलर में अधिग्रहित कर ली। अपने चरम पर संयंत्र प्रतिदिन लगभग 2,500 टन सीमेंट बनाता था।

बंदी की समयरेखा

1 अप्रैल 2026 को क्लिंकर आपूर्ति बंद होने के बाद उत्पादन रुक गया; 3 मई को फेरि्ट पावर प्लांट बंद हुआ; और औपचारिक लॉकआउट नोटिस के बाद 16 अगस्त 2026 तक शेष परिचालन बंद हो गया। कार्यबल में केवल 74 स्थायी कर्मचारी थे, जिन्हें सेवा-निवृत्ति लाभ मिले, जबकि शेष लगभग 1,500 संविदा कर्मचारी थे। संविदा कर्मचारी सदानंद हेस्सा के अनुसार अंतिम महीनों में काम महीने में केवल लगभग 15 दिन ही मिलता था। इस बंदी का असर 20-25 गांवों के लगभग 50,000 लोगों पर पड़ा है, जिनमें अधिकांश आदिवासी आबादी है।

विरोध प्रदर्शन

1 जुलाई 2026 को लगभग 1,200 श्रमिकों, निवासियों और यूनियन सदस्यों ने झींकपानी से चार्डबासा के उपायुक्त कार्यालय तक 17 किलोमीटर का मार्च निकाला और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जापन सौंपा। एसीसी बचाओ संघर्ष समिति की मुख्य मांग थी कि फैक्ट्री बंद न की जाए। बंदी के समय तक संविदा कर्मचारियों के मुआवजे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर लोगों की सहायता और आगे संभावित पलायन को लेकर



असीत पाठक,
प्रधान संपादक देश दर्पण संवाद



“आप इस धरती पर आनंदित होने और दूसरों को आनंदित करने आए हैं। प्रसन्न रहना सीखिए, क्योंकि प्रसन्नता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है।”

- श्री परमहंस योगानंद जी

क्या आज के दौर में वाकई एक नए समाचार पत्र की आवश्यकता थी?

जी हाँ, अत्यंत आवश्यकता थी, इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु यह समाचार पत्र लाया गया है। लेकिन एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से दिमाग में उठता है कि जब देश में पहले से ही इतने सारे समाचार पत्र कार्य कर रहे हैं और आज इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल जगत का दौर है, तो क्या एक नया समाचार पत्र अपने आप के साथ न्याय कर पाएगा? क्या वह अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध कर पाएगा?

इसका जवाब तो वह ही देगा, लेकिन मैंने इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित विचारों और विश्लेषण के साथ देने का प्रयास किया है—

- आवश्यकता थी भारत की प्राचीन सांस्कृतिक खुराबू से संपूर्ण भारत को महकाने और उसकी सुगंध को देश-दुनिया तक पहुँचाने की।
- आवश्यकता थी यह तथ्य सार्वजनिक करने की, ‘भारत का इतिहास केवल गुलामी काल का नहीं, बल्कि लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी गौरवशाली सभ्यता का स्वर्णिम इतिहास है ।
- आवश्यकता थी यह बतलाने की ‘भारत का स्वर्णिम भविष्य यहां से शुरू होकर आने वाले कई हजार वर्ष तक चलेगा।
- आवश्यकता थी भारत का युवा वर्ग, महिला वर्ग तथा हर आयु और हर वर्ग के नागरिक—इन सभी की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और विचारों का न्यायपूर्ण विश्लेषण करने तथा उनको उचित प्रतिनिधित्व देने की।
- आवश्यकता थी भारत के युवा वर्ग को यह परिचय कराने और विश्वास दिलाने की कि भारत मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक केवल 200 वर्षों तक ही आर्थिक महाशक्ति नहीं रहा है। भारत की आर्थिक शक्ति का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। आज भारत एक बार फिर आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है और हमारा विश्वास है कि यह यात्रा आने वाले कई हजार वर्ष तक निरंतर आगे बढ़ती रहेगी।
- आवश्यकता थी युवा वर्ग तथा कार्यशील वर्ग को यह एहसास दिलाने ने की कि भारत अब ऐसी विकास यात्रा पर आगे बढ़ चुका है, जहाँ आने वाले समय में उद्योग, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार के अवसरों की संभावनाएँ लगातार बढ़ेंगी। भारत व्यापार और उद्योग की दुनिया में कभी महाशक्ति था, आज भी उसकी क्षमता उतनी ही व्यापक



है और आने वाले समय में भी वह आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी विश्वास के साथ ‘देश दर्पण संवाद’ का संकल्प है कि भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, रोजगार और विकास की संभावनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारीयों युवा और कार्यशील वर्ग तक पहुँचाएगा—ताकि वे केवल परिस्थितियों के दर्शक न रहें, बल्कि भारत की आर्थिक विकास यात्रा के सक्रिय सहभागी बनें।

7. आज आवश्यकता थी एक ऐसे समाचार पत्र की जो ब्लैकमेलिंग वाली पत्रकारिता से ऊपर उठकर भारत की बात करे, भारतीयों की बात करे, भारत के स्वर्णिम इतिहास और स्वर्णिम भविष्य की बात करे तथा देश को आगे ले जाने वाली एक सकारात्मक राह दिखाए।

8. आवश्यकता थी ऐसी पत्रकारिता की, जो आज के भारत के राजनीतिक परिदृश्य का निष्पक्ष और यथार्थ आकलन करे; पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता हो या प्रतिपक्ष—हर राजनीतिक शक्ति का वास्तविक स्वरूप जनता के सामने रखने का साहस रखे। ऐसी पत्रकारिता, जिसमें न किसी का भय हो, न किसी का पक्षपात और न कोई निजी स्वार्थ—केवल देशहित और सत्य के प्रति निष्ठा हो।

9. और आवश्यकता थी ऐसे समाचार पत्र की भी जो केवल प्रिंट मीडिया तक सीमित न रहे, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल मीडिया के सभी आधुनिक आयामों के साथ मजबूती से अपनी एक विशिष्ट जगह और पहचान बनाए।

इसके साथ ही कुछ संकल्पों की भी आवश्यकता थी जो हम आज इस समाचार पत्र के माध्यम से ले रहे हैं, हम संकल्प लेते हैं कि—

- हमारा देश दर्पण भारत की प्रगति, विकास यात्रा का ही संवाद करेगा।
- हम सत्य को सर्वोच्च स्थान देते हुए पत्रकारिता को भय और स्वार्थ से मुक्त रखने का प्रयास करेंगे।
- हम युवा भारत को केन्द्र में रखते हुए भारत के स्वर्णिम इतिहास व स्वर्णिम भविष्य को सम्मान के साथ सामने लाएंगे व महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज़ को स्थान देंगे।
- हम राजनीति का विश्लेषण करेंगे, राजनीतिक पक्षधरता नहीं।
- हम सनसनी से अधिक सार्थकता को महत्व देंगे।
- हम पत्रकारिता को ब्लैकमेलिंग का माध्यम नहीं बनने देंगे।
- हम भारत को केवल समस्याओं के देश के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे, समस्याओं के साथ समाधान की भी बात करेंगे।
- हम प्रिंट से डिजिटल तक नई पीढ़ी की

पत्रकारिता विकसित करेंगे।

प्रधान संपादक के रूप में मेरा व्यक्तिगत संकल्प

प्रधान संपादक के रूप में मेरा एक व्यक्तिगत संकल्प है कि मैं देश के युवाओं में आंतरिक शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और संकट का सामना करने की क्षमता जो सम्पूर्ण विश्व में भारतीय युवाओं में सर्वाधिक है को और विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य करूँगा। भारतीय युवाओं ने अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा व कौशल से पूरे विश्व को प्रभावित किया है।

मेरा मानना है कि किसी भी देश, समाज और परिवार पर जब संकट आता है, तो सबसे अधिक अपेक्षा उसके युवाओं से ही की जाती है। इसलिए केवल शारीरिक रूप से सक्षम या शिक्षित होना पर्याप्त नहीं है; युवाओं के भीतर मानसिक दृढ़ता, आत्मबल, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने का साहस होना भी उतना ही आवश्यक है। जीवन में आने वाले संकटों से भागना समाधान नहीं कायरता है।

यह वही भारत है जिसकी धरती ने छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं को जन्म दिया है। हमारी परंपरा हमें सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, उससे आँख मिलाकर खड़ा होना ही सच्चे साहस की पहचान है।

आंतरिक शक्ति केवल उपदेश से पैदा नहीं होती। इसके लिए सही विचार, अनुशासन, आत्मचिंतन, आध्यात्मिक चेतना, अच्छे साहित्य, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों और जीवन में सही आदर्शों की आवश्यकता होती है। मेरा प्रयास रहेगा कि युवाओं को ऐसे उपयोगी साधनों और विचारों से परिचित कराया जाए, जो उन्हें भीतर से और अधिक मजबूत बना सकें।

क्योंकि मेरा विश्वास है—

मजबूत राष्ट्र का निर्माण केवल प्रतिभाशाली युवाओं से नहीं, बल्कि मजबूत चरित्र और मजबूत आंतरिक शक्ति वाले युवाओं से होता है। इन्हीं उम्मीदों, इन्हीं आवश्यकताओं और इन्हीं विचारों के साथ, एक नई सोच, नई उर्जा और नए उत्साह के साथ यह समाचार पत्र भारतीय प्रिंट जगत तथा इलेक्ट्रॉनिक /डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने और नई ऊँचाइयों छूने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

टेक समाधान या व्यवधान: कैसे जनरेटिव एआई आईटी सेक्टर के नियम बदल रहा है और विज्ञान-कथा (Sci-Fi) की कल्पना को हकीकत बना रहा है



तनय की दृष्टि से...

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब आधिकारिक तौर पर सिर्फ एक कॉरपोरेट चर्चा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि हमारे समय का सबसे बड़ा आर्थिक चालक बन चुका है। घंटों के जटिल और विश्लेषणात्मक कार्यों को मिनटों में समेटने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाने वाली यह जादुई तकनीक, कॉर्पोरेट संरचनाओं को तेजी से नया आकार दे रही है। कुछ समय पहले तक तकनीकी विशेषज्ञों के बीच यह एक दार्शनिक बहस का विषय था कि क्या मानवरूपी रोबोट (ह्यूमनॉइड्स) और एआई इंसानी कामकाज पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। आज हम इन बातों को अपनी आँखों के सामने सच होते देख रहे हैं, जो आधुनिक औद्योगिक इतिहास के सबसे अनोखे दौर का संकेत है।

हॉलीवुड की कल्पना जो आज हकीकत बनती दिख रही है
इससे पहले कि एआई ने कॉर्पोरेट वर्कफ्लो को ऑटोमेट (स्वाचलित) करना शुरू किया, संवेदनशील और सोचने वाली मशीनों की अवधारणा हॉलीवुड फिल्म निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा विषय हुआ करती थी। दशकों तक, दूरदर्शी निर्देशकों ने ह्यूमनॉइड्स को सिनेमाई उत्कृष्ट कृतियों के लिए एक मुख्य विषय के रूप में इस्तेमाल किया। घोस्ट इन द शेल (1995) जैसी फिल्मों ने साइबरनेटिक्स और मानवीय चेतना के बीच धुंधली होती रेखाओं की पड़ताल की, जबकि ए.आई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (2001) ने भावनाओं वाले एक रोबोटिक बच्चे की कहानी को गहराई से दिखाया। आई, रोबोट (2004) और सभीक्षकों द्वारा सराही गई एक्स मशिना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने ऐसी chetawaniyan दीं जहाँ एंड्रॉइड इंटेलिजेंस अपने मानव निर्माताओं से आगे निकल जाती है।

आज, कॉर्पोरेट जगत यह महसूस कर रहा है कि जो कभी सिर्फ विज्ञान-कथाओं के दायरे में था, वह अब आधिकारिक तौर पर एक वास्तविकता बन चुका है। वर्तमान स्थिति: बदलती मांग और कठिन होती भर्ती प्रक्रिया-अगर हम मौजूदा व्यापक आर्थिक परिदृश्य को देखें, तो इस ऑटोमेशन (स्वाचालन) की लहर का सीधा असर इंफर्मेेशन टेक्नोलॉजी (IT) और कंप्यूटर साइंस कंपनियों पर पड़ा है। कॉर्पोरेट जगत में आए इस बदलाव को इन मुख्य बिंदुओं से समझा जा सकता है:

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा॥



रत्ना पाठक की कलम से...

जय गणेश देवा
जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। पूरे भारत में इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसकी विशेष धूम देखने को मिलती है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। इस अवसर पर घरों और सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। कई दिनों तक उनकी पूजा, आरती और भक्ति से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद श्रद्धापूर्वक गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस तरह गणेश उत्सव भक्ति, आनंद और सामूहिक उत्साह का पर्व बन जाता है।
गणेश उत्सव को आधुनिक सार्वजनिक स्वरूप देने का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी दिया जाता है। उन्होंने इस उत्सव को सामाजिक एकता और जन-जागरण का माध्यम बनाया। उनके प्रयासों से गणेश उत्सव लोगों को एक साथ लाने और समाज में जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण अवसर बन गया।
लेकिन मेरे लिए गणपति बप्पा केवल एक त्योहार का हिस्सा नहीं हैं। गणपति बप्पा हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए जब भी हम कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं, सबसे पहले गणपति जी का स्मरण करते हैं—

“नया काम शुरू करूँ तो पहले तेरा ही नाम नू गणपति बप्पा—तेरे आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ूँ”
भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। वे विघ्नहर्ता हैं, अर्थात हमारे जीवन की बाधाओं और संकटों को दूर करने वाले। साथ ही, वे बुद्धि, विद्या और विवेक के अधिपति भी हैं।
यदि हम गणपति जी के स्वरूप को ध्यान से देखें, तो उनके प्रत्येक अंग में जीवन के लिए एक गहरा संदेश छिपा हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले, उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं कि जीवन में बोलने से अधिक जरूरी है—ध्यान से सुनना। जब हम दूसरों की बात धैर्यपूर्वक सुनते हैं, तभी सही निर्णय ले पाते हैं।
उनकी छोटी आँखें एकाग्रता का संदेश देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें और रास्ते की छोटी-बड़ी परेशानियों से विचलित न हों।
उनका बड़ा मस्तक विशाल सोच और ज्ञान का प्रतीक है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम छोटी-छोटी बातों से ऊपर उठकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाएँ और हर परिस्थिति को समझदारी से देखें।
इसी तरह, उनका बड़ा उदर हमें जीवन की अछी-बुरी परिस्थितियों को स्वीकार करने और उन्हें धैर्यपूर्वक संभालने की सीख देता है। उनकी एकदंत हड्डी सिखाती है कि जीवन में आवश्यक बातों को अपनाना चाहिए और अनावश्यक बातों को छोड़ना सीखना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए यह समझना जरूरी है कि क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्या नहीं।
उनके हाथ में मौजूद अंकुश नियंत्रण और जागरूकता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
वही, उनका पाश हमें अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं और

इंजीनियरों की मांग के मानदंडों में बदलाव: सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंजीनियरों को पिछले दो दशकों में बाजार में जो पारंपरिक बहुत हासिल थी, उसके मानदंडों में अब बड़ा बदलाव आया है। अब केवल बुनियादी कोडिंग के भरोसे काम नहीं चल रहा है। बेहद कठिन हुई भर्ती प्रक्रिया: किसी भी टेक कंपनी में नौकरी पाना अब पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स ने अब हायरिंग के मानकों को बहुत ऊंचा कर दिया है। इंटरव्यू राउंड के दौरान अब अत्यधिक एडवांस्ड (उच्च स्तरीय) और वैचारिक सवाल पूछे जा रहे हैं। उम्मीदवारों से उम्मीदी की जाती है कि उन्हें कई आधुनिक तकनीकों की गहरी समझ हो, जिसने एंटी-लेवल भर्ती को काफी कड़ा बना दिया है। भविष्य की राह: एआई और मशीन लर्निंग का नया सवेरा हालाँकि, यह चल रहा बदलाव एक क्लासिक आर्थिक प्रवृत्ति का अनुसरण करता है: जब एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा खुलता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भविष्य खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि इसे एआई और मशीन लर्निंग (ML) के इर्द-गिर्द आक्रामक रूप से फिर से तैयार किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट रणनीतियाँ अब पारंपरिक प्रोग्रामिंग से हटकर विशेष एआई विकास पर केंद्रित हो रही हैं। पूरी तरह से बाहरी सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहने के बजाय, कंपनियाँ तेजी से अपने खुद के कस्टमाइज्ड चैटबॉट विकसित कर रही हैं, जो उनके विशिष्ट डेटा सिस्टम के अनुकूल हों। इसके अलावा, यह बदलाव अब केवल तकनीकी क्षेत्र (Tech Sector) तक ही सीमित नहीं रह गया है। गैर-तकनीकी क्षेत्र-जैसे कि आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग, एफएमसीजी (FMCG), रिटेल और रेस्टोरेंट/होटल उद्योग-भी ग्राहक सेवा, सफाई चैन और डिजाइन वर्कफ्लो को बेहतर बनाने के लिए कस्टम चैटबॉट्स को सक्रिय रूप से अपना रहे हैं।

निष्कर्ष
यह मौजूदा बदलाव एक अकाट्य सच्चाई को रेखांकित करता है: पारंपरिक कोडिंग का दौर अब पीछे छूट रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के युग में प्रवेश कर चुकी है। जैसे-जैसे टेक कंपनियां ‘एआई-फ़स्ट’ भविष्य की ओर बढ़ रही हैं, प्रोफेशनल्स और बिजनेस दोनों का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी तेजी से खुद को बदलते हैं। इस नए इकोसिस्टम में, समय के साथ चलने की क्षमता ही आने वाले दिनों में इन कंपनियों का भविष्य निर्धारित करेगी।

अनावश्यक आसक्तियों को पहचानकर उनसे मुक्त होने की प्रेरणा देता है।
और उनका वाहन छोटा-सा मूषक हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएँ छोटी होते हुए भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं।
इस प्रकार, गणपति जी का स्वरूप केवल पूजा का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक सुंदर दर्शन भी है।

महिलाओं के लिए गणपति जी की सीख
अब मैं विशेष रूप से महिलाओं से कुछ कहना चाहूँगी। हम अक्सर अपने जीवन में परिवार और समाज की जिम्मेदारियाँ निभाते-निभाते स्वयं को भूल जाते हैं। लेकिन गणपति जी हमें सिखाते हैं कि बुद्धि, आत्मविश्वास और संतुलन के साथ अपना जीवन जीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गणपति जी का बड़ा मस्तक हमें संदेश देता है—बड़ा सोचो। उनके बड़े कान कहते हैं—सबकी सुनो, लेकिन निर्णय अपने विवेक से लो।
उनकी छोटी आँखें हमें प्रेरित करती हैं—अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ। और उनका शांत स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति केवल ऊँची आवाज़ में नहीं, बल्कि संयम, धैर्य और आत्मविश्वास में भी होती है। आज की महिलाएँ परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाने के साथ-साथ शिक्षा, व्यवसाय, नेतृत्व और समाज के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। इसलिए हमें गणपति जी से यह भी सीखना चाहिए कि दूसरों के लिए जीते हुए अपनी पहचान को कभी नहीं खोना है।
अपने सपनों को महत्व देना, अपनी बात सम्मानपूर्वक रखना और अपनी क्षमता पर विश्वास करना भी जीवन का आवश्यक हिस्सा है। गणेश चतुर्थी हमें केवल पूजा और उत्सव का संदेश नहीं देती, बल्कि ज्ञान, विवेक, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता की प्रेरणा भी देती है।

आज अनेक गणेश मंडल रक्तदान, वृक्षारोपण और जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसी सामाजिक गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। सार्वजनिक गणेश उत्सव समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। इससे आपसी प्रेम, सहयोग और भाईचारा मजबूत होता है। इसके साथ ही, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भक्ति प्रकृति के लिए नुकसान का कारण न बने। पर्यावरण-अनुकूल गणेश प्रतिमाओं और प्राकृतिक सजावट का उपयोग करके हम अपनी आस्था के साथ-साथ प्रकृति की रक्षा भी कर सकते हैं।

आइए, इस गणेश चतुर्थी पर हम केवल गणपति जी की प्रतिमा अपने घर में स्थापित न करें, बल्कि उनके ज्ञान, विवेक, धैर्य और सकारात्मकता को अपने जीवन में भी अपनाएँ।
आइए, हम सब मिलकर संकल्प लें—

**जहाँ अज्ञान है, वहाँ ज्ञान फैलाएँ।
जहाँ निराशा है, वहाँ आशा दें।
जहाँ बाधाएँ हैं, वहाँ हिम्मत से आगे बढ़ें।
और जहाँ जरूरत होगी, वहाँ समाज के लिए अपना योगदान दें।**

गणेश चतुर्थी भक्ति, ज्ञान, संस्कृति, प्रकृति और एकता का त्योहार है।

आइए, हम सब मिलकर इसे श्रद्धा, प्रेम और जिम्मेदारी के साथ मनाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, स्वच्छ और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित कर सकें।

**गणपति बप्पा मोरया! मंगल मूर्ति मोरया!
विघ्नहर्ता गणपति महाराज की जय!**

GeM के 10 साल: फाइलों के बोझ से आज़ाद हुआ सरकारी बाजार, खड़ा हुआ 20 लाख करोड़ का ‘स्मार्ट’ साम्राज्य



● प्रदीप सैनी

वह भी क्या दौर था, जब सरकारी दफ्तरों में एक कुर्सी या कंप्यूटर खरीदने के लिए टेंडर की मोटी-मोटी फाइलें धूल फांकती थीं। महीनों का इंतजार, बाबूगिरी का बोलबाला और अपारदर्शिता। इसी सुस्त व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए 9 अगस्त 2016 को ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (GeM- जेम) की शुरुआत हुई

थी। आज इस पोर्टल ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। यह दशक सिर्फ एक सरकारी वेबसाइट के विस्तार का नहीं, बल्कि देश में सरकारी खरीद के पूरे तौर-तरीके के बदलने का गवाह है। आज जेम महज एक ‘शॉपिंग वेबसाइट’ नहीं, बल्कि एक विशाल डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है। आंकड़े गवाह हैं— इस पर 25 लाख से ज्यादा विक्रेता (सेलर्स) और 1.37 लाख से अधिक सरकारी खरीदार जुड़े हैं। अब तक यहां 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का महा-कारोबार दर्ज हो चुका है। वर्जन 1.0 की बेसिक सुविधाओं से शुरू हुआ यह सफर आज GeM 3.0 के एडवांस दौर में है। तकनीक इतनी हावी है कि अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी अगर कुछ ठेकेदार गूट बनाकर (कार्टेल) कीमतें बढ़ाते हैं या सरकार को चूना लगाने की कोशिश

करते हैं, तो स्मार्ट सिस्टम तुरंत धांधली पकड़ लेता है। कागजों से निकलकर डिजिटल हुई इस व्यवस्था ने दशकों से सरकारी टेंडरों पर कुंडली मारकर बैठे रसूखदार ठेकेदारों की नींद उड़ा दी है। ...लेकिन इस नए बाजार का असली ‘सिंकदर’ कौन? इस 20 लाख करोड़ के सरकारी बाजार में आखिर बाजी किसने मारी? कैसे बिना किसी ‘अप्रोच’ या ‘जुगाड़’ के छोटे शहरों के युवाओं और स्टार्टअप्स ने सीधे सरकार को 65 हजार करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया? जेम से कैसे रातों-रात बदली नए उद्यमियों की किस्मत? (पढ़िए हमारी इस विशेष सीरीज के दूसरे अंक में.)



महाकाल के भक्त, मध्य प्रदेश की शक्ति: संस्कृति और सुशासन से ‘नया एमपी’ गढ़ रहे डॉ. मोहन यादव

उज्जैन दक्षिण की गलियों से निकलकर प्रदेश की बागडोर संभालने वाले डॉ. मोहन यादव ने महज कुछ ही महीनों में 30 लाख करोड़ के निवेश, ‘रीजनल इंडस्ट्री कॉन्वलेव’ की अभिनव पहल और महाकाल लोक की तर्ज पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण से मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बना दिया है।

● प्रकाश त्रिपाठी, शिवम् शुक्ला

भारतीय राजनीति में ऐसे विरले ही उदाहरण मिलते हैं, जहां सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति अपनी जड़ों और अपनी आस्था से इतना गहराई से जुड़ा हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसी विरल परंपरा के संवाहक हैं। काल के भी काल, बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन से निकलकर मध्य प्रदेश के साढ़े आठ करोड़ नागरिकों के कल्याण का बीड़ा उठाने वाले डॉ. यादव आज प्रदेश में ‘सुशासन और संस्कृति’ के नए युग का सूत्रपात कर रहे हैं।

विद्यार्थी परिषद (ABVP) के संघर्षों से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संस्कारों की भट्ठी में तपकर कुंदन बने डॉ. मोहन यादव का विजन स्पष्ट है— मध्य प्रदेश को केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी देश का सिरमौर बनाना। आस्था और संस्कृति का महा-अभियान: सिंहस्थ 2028 की तैयारी

मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही डॉ. यादव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विकास की कोई भी इमारत संस्कृति की नींव के बिना अधूरी है। उज्जैन का ‘श्री महाकाल लोक’ आज पूरे विश्व में आस्था और अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक बन चुका है। इसी तर्ज पर अब पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों का कार्याकल्प हो रहा है।

मई 2028 में उज्जैन में होने वाले ‘सिंहस्थ महाकुंभ’ को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्षिप्रा के शुद्धिकरण, नए घाटों के निर्माण, मालवा क्षेत्र में फोर-लेन और सिक्स-लेन सड़कों का जाल और इंदौर-उज्जैन मेट्रो प्रोजेक्ट पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है। ‘श्रीराम वन गमन पथ’ और ‘श्रीकृष्ण पाथेय’ जैसी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक जड़ों को सींचा जा रहा है। 30 लाख करोड़ का महा-निवेश: विकास का ‘रीजनल मॉडल’ डॉ. मोहन यादव की सबसे बड़ी प्रशासनिक सफलता औद्योगिकीकरण का विकेंद्रीकरण है। विकास केवल भोपाल या इंदौर तक सीमित न रहे, इसके लिए उन्होंने ‘रीजनल इंडस्ट्री कॉन्वलेव’ (RIC) की ऐतिहासिक शुरुआत की। उज्जैन से शुरू हुआ यह सिलसिला जबलपुर, रीवा, ग्वालियर और सागर तक पहुंचा है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और हालिया दुबई दोरे के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को मध्य प्रदेश आमंत्रित किया है। पारदर्शी नीतियों के चलते प्रदेश में 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

किसान, युवा और नारी शक्ति का उत्थान कृषि प्रधान मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। ऐतिहासिक ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना’ और नई सिंचाई योजनाओं से प्रदेश का सिंचित रकबा 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने वाला है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से करोड़ों माताओं-बहनों के स्वातंत्र्य में सम्मान निधि पहुंचाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। वहीं, युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा और ‘सीखो-कमाओ योजना’ के जरिए उन्हें ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार किया जा रहा है।

कर्मभूमि ‘उज्जैन दक्षिण’: जनता का अटूट विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सफलता की नींव उनकी अपनी विधानसभा ‘उज्जैन दक्षिण’ में छुपी है। वर्ष 2013 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने इसे विकास का एक मॉडल बना दिया है। एक समय जो क्षेत्र केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित था, आज डॉ. यादव के प्रयासों से वह उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा हब बन चुका है। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लेकर नई सड़कों के निर्माण तक, उज्जैन दक्षिण की जनता ने अपने जननायक को जो प्यार दिया, आज उसी ऊर्जा से वे पूरे प्रदेश को सींच रहे हैं।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद: “हमारा उद्देश्य सिर्फ इमारतें खड़ी करना नहीं, बल्कि प्रदेश की आत्मा को जगाना है। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हम मध्य प्रदेश को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित कर रहे हैं।” सुशासन का संकल्प: “सरकार का हर कदम, हर योजना पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति (अंत्योदय) की भलाई के लिए है। कानून व्यवस्था के मामले में हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं; अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है।”

औद्योगिक विकास: “हम मध्य प्रदेश को केवल कृषि प्रधान नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर हाथ को



काम, हमारा मूल मंत्र है।” अपनी सादगी, त्वरित निर्णय क्षमता और सर्व-समावेशी सोच के चलते डॉ. मोहन यादव केवल सत्ता का संचालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगले 25 वर्षों के ‘स्वर्णिम मध्य प्रदेश’ की मजबूत नींव रख रहे हैं। महाकाल के इस परम भक्त के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्रांति: ‘मानव संसाधन’ का अभूतपूर्व विकास डॉ. मोहन यादव सरकार का विजन केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। ‘स्वस्थ मध्य प्रदेश, शिक्षित मध्य प्रदेश’ के मंत्र पर अभूतपूर्व तेजी से कार्य हुआ है।

पीएम कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस और सीएम राइज स्कूल: प्रदेश के सभी 55 जिलों में ‘पीएम कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस’ की स्थापना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। जहां युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा और रोजगारपरक कोर्सेस मिल रहे हैं। इसके साथ ही, ‘सीएम राइज’ स्कूलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्मार्ट क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है।

हर जिले में मेडिकल कॉलेज और एयर एंबुलेंस: “कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में न रहे”, इस संकल्प के साथ प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी ‘पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा’ ने दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में संजीवनी का काम किया है। अब दूरदराज के इलाकों से गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट कर बड़े अस्पतालों तक मुफ्त पहुंचाया जा रहा है, जो सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है।

जनजातीय गौरव और वनांचलों का कार्याकल्प मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा जनजातीय आबादी वाला राज्य है। डॉ. मोहन यादव ने इस वर्ग को केवल वोटबैंक नहीं, बल्कि विकास का साझीदार माना है।

पेसा (PESA) एक्ट का जमीनी क्रियान्वयन: जनजातीय समाज को जल, जंगल और जमीन का वास्तविक अधिकार देते हुए ग्राम सभाओं को सशक्त किया गया है।

सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन और वनोपज: वनांचलों में सिकल सेल की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा, तैदूपात संग्रहकों के मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि और ‘श्री अन्न’ (मोटे अनाज) को प्रमोट

कर जनजातीय किसानों की आय दोगुनी करने का सफल प्रयास किया गया है। महापुरुषों का सम्मान: रानी दुर्गावती, टंट्या भील और बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय नायकों के भव्य स्मारक और उनके नाम पर विश्वविद्यालयों की स्थापना कर सरकार ने जनजातीय गौरव को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया है।

एविएशन, लॉजिस्टिक्स और आईटी: युवाओं के सपनों की उड़ान मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस भौगोलिक लाभ (Geographical Advantage) को प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है।

पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा: प्रदेश के प्रमुख शहरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा) को जोड़ते हुए ‘इंटर-स्टेट एविएशन’ (राज्यों के भीतर हवाई सेवा) की शुरुआत की गई है। इससे न केवल पर्यटन को पंख लगे हैं बल्कि व्यापारिक आवागमन भी सुलभ हुआ है। भारत का लॉजिस्टिक्स हब: शानदार हाईवे नेटवर्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोरों के कारण मध्य प्रदेश आज ई-कॉमर्स और सप्लाय चेन कंपनियों के लिए देश का सबसे बड़ा ‘लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब’ बन चुका है।

ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण: भविष्य का ‘सस्टेनेबल’ मध्य प्रदेश जब दुनिया जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से जूझ रही है, तब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश को दिशा दिखा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में सिरमौर: रीवा, नीमच, अगर और शाजापुर के विशाल सोलर पार्क्स से पैदा होने वाली बिजली से न केवल मध्य प्रदेश रोशन हो रहा है, बल्कि दिल्ली मेट्रो तक को बिजली सप्लाई की जा रही है।

सोलर सिटी और ग्रीन हाइड्रोजन: सांची को देश की पहली ‘सोलर सिटी’ बनाने के बाद अब अन्य शहरों को भी इस मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। सरकार की नई ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति’ और ई-मोबिलिटी (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) पर जोर प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केन-बेतवा के साथ-साथ नर्मदा संरक्षण के लिए करोड़ों पौधे लगाने का महाभियान मुख्यमंत्री की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विस्तार: श्री कृष्ण पाथेय से अद्वैत लोक तक उज्जैन में ‘श्री महाकाल महालोक’ की सफलता के बाद प्रदेश के अन्य

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार मुख्यमंत्री के विजन का अहम हिस्सा है।

श्री कृष्ण पाथेय और राम वन गमन पथ: भगवान श्री कृष्ण ने मध्य प्रदेश (उज्जैन के सांदीपनि आश्रम) में जहां-जहां शिक्षा ग्रहण की और समय बिताया, उन सभी स्थानों को ‘श्री कृष्ण पाथेय’ के रूप में एक तीर्थ सर्किट की तरह विकसित किया जा रहा है। इसी तरह चित्रकूट से लेकर प्रदेश के अन्य हिस्सों तक ‘श्री राम वन गमन पथ’ का निर्माण आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बन रहा है। एकत्म धाम (ओकारेश्वर) और ओरछा: ओकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा (Statue of Oneness) और ‘अद्वैत लोक’ का निर्माण पूरी दुनिया के वेदांत विचारकों को मध्य प्रदेश खींच रहा है। ओरछा में ‘श्री रामराज्य लोक’, दतिया में ‘पीतांबरा पीठ’ और सलकनपुर में ‘देवी महालोक’ का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

स्मार्ट और सुरक्षित शहर: विकास का नया पैमाना मेट्रो और अर्बन मोबिलिटी: भोपाल और इंदौर मेट्रो का तेजी से विस्तार हुआ है। शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए प्लाईओवर्स और एलिवेटेड कॉरिडोरों का जाल बिछाया गया है। स्वच्छता का सरताज: इंदौर का लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आना और अब प्रदेश के अन्य शहरों (भोपाल, उज्जैन आदि) का भी टॉप रैंकिंग में अपनी जगह बनाना, इस बात का प्रमाण है कि स्वच्छता अब मध्य प्रदेश के नागरिकों के स्वभाव में शामिल हो गई है।

निष्कर्ष: ‘विजन 2047’ और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नवंबर 2023 से लेकर सितंबर 2026 तक की यह यात्रा महज एक सरकारी कार्यकाल का ब्यौरा नहीं है, बल्कि यह एक ‘ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप’ (परिवर्तनकारी नेतृत्व) की मिसाल है। डॉ. मोहन यादव ने अपने शांत लेकिन बेहद आक्रामक और परिणामोन्मुखी विजन से यह साबित कर दिया है कि जब नेतृत्व की नीयत साफ हो, तो नीतियां चमत्कार करती हैं।

आज का मध्य प्रदेश बीमार राज्य का तमगा बहुत पीछे छोड़ चुका है। वह अब केवल ‘विकासशील’ नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत @ 2047’ के संकल्प में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है। डॉ. मोहन यादव के सुशासन, उनके सांस्कृतिक बोध और उनके औद्योगिक विजन ने एक ऐसे ‘स्वर्णिम मध्य प्रदेश’ की नींव रख दी है, जिस पर आने वाली कई पीढ़ियां गर्व करेंगी।

अमेरिका और कनाडा के बीच गहराया ‘ट्रेड वॉर’, कनाडाई डेयरी उत्पादों पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली । दुनिया के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और पड़ोसी देश, अमेरिका और कनाडा के बीच एक बार फिर व्यापारिक तनाव (ट्रेड वॉर) गहरा गया है। आयात शुल्क (टैरिफ) को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव इतना बढ़ गया है कि अमेरिका ने सख्त कदम उठाते हुए कनाडा से आने वाले डेयरी (दूध से बने) उत्पादों और कई अन्य सामानों के आयात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं।

पृष्ठभूमि: दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों का इतिहास

अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार सदियों पुराना और बेहद गहरा रहा है। दोनों देश एक-दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में गिने जाते हैं, और सीमा के आर-पार योजना अरबों डॉलर का कारोबार होता है। ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पाद और डेयरी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि जब भी दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेद उभरते हैं, तो उसका असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी दिखाई देता है। डेयरी क्षेत्र हमेशा से इन दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि कनाडा अपने घरेलू डेयरी उद्योग को एक विशेष कोटा और टैरिफ व्यवस्था के जरिए संरक्षण देता आया है, जबकि अमेरिका इसे अनुचित व्यापार बाधा मानता रहा है।

अमेरिका का आरोप है कि कनाडा अपने डेयरी बाजार को जरूरत से ज्यादा सुरक्षा दे रहा है, जिससे अमेरिकी किसानों को वहां अपना सामान बेचने में नुकसान हो रहा है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि यह असंतुलन लंबे समय से बना हुआ है और इससे उनके घरेलू डेयरी उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी बात से नाराज होकर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडाई उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का यह सख्त फैसला लिया है। दूसरी ओर, कनाडा का पक्ष यह रहा है कि उसकी नीतियां घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई हैं, और वह अपने बाजार को पूरी तरह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कनाडाई

अधिकारियों का तर्क है कि हर देश को अपने रणनीतिक क्षेत्रों – जैसे खाद्य सुरक्षा और कृषि – की रक्षा करने का अधिकार है, और यह कोई नई या असामान्य नीति नहीं है।

डेयरी सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर

इस पूरे विवाद के केंद्र में डेयरी सेक्टर है। कनाडा में दूध, चीज (पनीर) और मक्खन जैसे उत्पादों को लेकर बेहद सख्त नियम हैं, जिन्हें वहां की सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी मानती है। यह व्यवस्था दशकों से चली आ रही है और कनाडा के घरेलू डेयरी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से एक हद तक बचाती है।

अमेरिका लंबे समय से यह मांग कर रहा था कि कनाडा अपने बाजार को अमेरिकी डेयरी किसानों के लिए और खोले, ताकि अमेरिकी उत्पाद बिना किसी बड़ी बाधा के कनाडा में बिक सकें। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया। जब बातचीत से हल नहीं निकला, तो अमेरिका ने कनाडा के कई उत्पादों की अपने देश में एंट्री पर रोक लगा दी। इस कदम को अमेरिका की तरफ से एक दबाव बनाने वाली रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि कनाडा बातचीत की मेज पर वापस आए और अपनी नीतियों में बदलाव करे।

डेयरी के अलावा किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है असर?

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है, तो इसका दायरा सिर्फ डेयरी तक सीमित नहीं रहेगा। कृषि से जुड़े अन्य उत्पाद, लकड़ी और इमारती सामान (लम्बर), ऊर्जा निर्यात और यहां तक कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र भी इस टकराव की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि व्यापारिक विवादों में अक्सर एक क्षेत्र से शुरू हुई तनावतनी धीरे-धीरे कई अन्य क्षेत्रों तक फैल जाती है।

अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर क्या होगा प्रभाव?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यापारिक युद्ध का नुकसान दोनों देशों को उठाना पड़ेगा, और इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है।

महंगाई का डर: जब एक देश दूसरे देश के सामान पर टैक्स लगाता है या रोकता है, तो बाजार में चीजों की कमी हो जाती है, जिससे उन उत्पादों के दाम बढ़ जाते हैं। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। डेयरी उत्पादों की कीमतों में उछाल दोनों ही देशों के बाजारों में देखने को मिल सकता है, जिससे घरेलू बजट प्रभावित होगा।

व्यापारियों को नुकसान: जो कंपनियां आयात-निर्यात के कारोबार में लगी हैं, उनके मुनाफे में कमी आएगी और सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) प्रभावित होगी। छोटे और मझोले व्यापारी, जो सीमा पार व्यापार पर निर्भर हैं, इस टकराव से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।

रोजगार पर असर: डेयरी और संबंधित उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों और किसानों की आजीविका पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि उत्पादन और निर्यात में कमी से कारोबार सिकुड़ सकता है। कनाडा के कई ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था डेयरी उद्योग पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए वहां इसका असर और गहरा हो सकता है।

निवेशकों में अनिश्चितता: व्यापारिक तनाव अक्सर शेयर बाजार और निवेशकों के भरोसे को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अनिश्चितता के माहौल में कंपनियां बड़े फैसले लेने से बचती हैं। इसका असर दोनों देशों की मुद्राओं (करेंसी) पर भी देखने को मिल सकता है।

वैश्विक बाजार पर असर: चूंकि अमेरिका और कनाडा दोनों ही वैश्विक व्यापार व्यवस्था के अहम हिस्सेदार हैं, इसलिए इस टकराव का असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अन्य देश, जो इन दोनों के साथ व्यापार करते हैं, वे भी



इस अस्थिरता से अछूते नहीं रहेंगे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के टकराव से तीसरे देशों को भी एक मौका मिल सकता है कि वे उस बाजार में अपनी पैठ बनाएं, जहां से अमेरिका या कनाडा को झटका लगा है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के अधिकारी इस मसले को सुलझाने के लिए संपर्क में बताए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। अर्थशास्त्रियों की नजर इस बात पर है कि क्या यह विवाद जल्दी सुलझ जाएगा, या फिर कनाडा भी अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करेगा।

अगर तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर वैश्विक व्यापार पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा दोनों ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के अहम स्तंभ माने जाते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देश इस टकराव को बातचीत के जरिए सुलझाते हैं, या यह विवाद और लंबा खिंचता है। जानकारों का कहना है कि दोनों देशों की आपसी निर्भरता को देखते हुए किसी न किसी स्तर पर समझौता होना तय माना जा रहा है, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, यह कहना फिलहाल मुश्किल है।

क्या है पूरा विवाद?

सरल शब्दों में समझें तो ‘ट्रेड वॉर’ तब होता है जब एक देश दूसरे देश से आने वाले सामानों पर टैक्स (टैरिफ) बढ़ा देता है या रोक लगा देता है, ताकि उसके अपने देश के किसानों और व्यापारियों को नुकसान न हो। यह एक तरह की आर्थिक रणनीति है, जिसका इस्तेमाल देश अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए करते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान यह भी होता है कि दोनों तरफ के व्यापार और उपभोक्ता प्रभावित होते हैं। अमेरिका का आरोप है कि कनाडा अपने डेयरी बाजार को जरूरत से ज्यादा सुरक्षा दे रहा है, जिससे अमेरिकी किसानों को वहां अपना सामान बेचने में नुकसान हो रहा है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि यह असंतुलन लंबे समय से बना हुआ है और इससे उनके घरेलू डेयरी उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

NSE का बड़ा आईपीओ जल्द बाजार में



नई दिल्ली । भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का करीब ₹30,000 करोड़ का आईपीओ 18 सितंबर को खुल सकता है और 25 सितंबर को इसकी लिस्टिंग की उम्मीद है। अगर यह इश्यू इसी आकार का रहता है, तो यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है, जो निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

NSE, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जहां रोजाना करोड़ों रुपये के शेयरों का कारोबार होता है। लंबे समय से इसके आईपीओ को लेकर बाजार में चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन नियामकीय प्रक्रियाओं और अन्य औपचारिकताओं के चलते इसमें देरी होती रही। अब जाकर यह प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है।

इस बीच, घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। Nifty लगातार दूसरे दिन गिरकर जुलाई के निचले स्तर के करीब पहुंच गया है, और टेक्निकल इंडिकेटर्स में भी कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं, जिसके

चलते 23,635 का स्तर बाजार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे माहौल में NSE के आईपीओ की टाइमिंग को लेकर भी बाजार जानकारों की अलग-अलग राय सामने आ रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बाजार में स्थिरता बनी रहती है, तो यह आईपीओ रिले और संस्थागत दोनों तरह के निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हो सकता है, क्योंकि खुद स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदने का मौका बहुत कम मिलता है। हालांकि, अंतिम इश्यू साइज, प्राइस बैंड और अन्य जरूरी जानकारियों को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, जो आने वाले दिनों में सामने आ सकती है।

NSE का यह आईपीओ ऐसे समय आ रहा है जब घरेलू बाजार पहले से दबाव में है, जिससे निवेशकों की नजर लिस्टिंग गेन पर टिकी रहेगी। बाजार जानकारों का कहना है कि एक्सचेंज की मजबूत बैलेंस शीट और स्थिर मुनाफे को देखते हुए यह इश्यू भारी सब्सक्रिप्शन आकर्षित कर सकता है, बशर्ते सेबी से अंतिम मंजूरी समय पर मिल जाए।

स्थानीय मुद्रा व्यापार: भारत ने ब्रिक्स मुद्रा के प्रस्ताव को खारिज किया, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का समर्थन किया

नई दिल्ली । स्थानीय मुद्रा व्यापार: भारत ने ब्रिक्स मुद्रा के प्रस्ताव को खारिज किया, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का समर्थन किया विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) सुधाकर दलेला ने शनिवार को कहा कि वर्तमान में एक सामान्य ब्रिक्स मुद्रा पेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि लेनदेन लागत को कम करने के एक तरीके के रूप में स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को निपटाने पर बातचीत जारी रहेगी।

नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दलेला ने कहा, “अभी के लिए, ब्रिक्स में किसी ब्रिक्स मुद्रा का कोई प्रस्ताव नहीं है।” उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ब्रिक्स देश सीमा पार भुगतानों को मजबूत करने और सदस्य देशों के बीच व्यापार निपटान को अधिक कुशल बनाने पर चर्चा जारी रखे हुए हैं।

स्थानीय मुद्रा निपटान जारी रहेगा

दलेला ने कहा कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटाने पर चर्चा ब्रिक्स में कुछ समय से चल रही है और यह कोई नई पहल नहीं है। उन्होंने कहा, “स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान पर ब्रिक्स में कुछ समय से बातचीत चल रही है: यह कोई नया विषय नहीं है।” उन्होंने स्थानीय मुद्रा निपटान को द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक व्यावहारिक तंत्र बताया और कहा कि इसका उद्देश्य मौजूदा वैश्विक भुगतान और निपटान ढांचे को बदलना नहीं है। दलेला ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि स्थानीय मुद्रा निपटान द्विपक्षीय व्यापार में लेनदेन लागत को कम करने का एक व्यावहारिक तंत्र है। इसे वैश्विक भुगतान और निपटान प्रणाली के पूरक के रूप में प्रोत्साहित किया गया है, जिससे सभी देशों में समग्र

वैश्विक व्यापार में सुधार होगा।”

नई दिल्ली घोषणापत्र में ब्रिक्स की स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार निपटान और निवेश को बढ़ावा देने पर चल रही चर्चाओं को भी स्वीकार किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान किया गया और यह माना गया कि इसके लिए कोई एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण (one-size-fits-all ap-proach) नहीं हो सकता। घोषणापत्र में कहा गया है कि ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स (BPTF) भुगतान और संदेश चैनलों की सीमा पार पारस्परिकता (interoperability) का अध्ययन कर रहा है। इसने टास्क फोर्स को व्यावहारिक भुगतान समाधानों की दिशा में काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जो “तेज, कम लागत वाले, अधिक सुलभ, कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित” हों।

आसान सीमा पार भुगतानों पर जोर

स्थानीय मुद्रा निपटान पर ध्यान केंद्रित करना सीमा पार व्यापार और भुगतान में सुधार के व्यापक ब्रिक्स प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि, दलेला की टिप्पणियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये चर्चाएं वर्तमान में एक एकल ब्रिक्स मुद्रा के निर्माण से जुड़ी नहीं हैं। शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के नेताओं के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भी अधिक आर्थिक सहयोग और स्थानीय मुद्राओं के व्यापक उपयोग पर जोर दिया था। पेजेशकियान ने ब्रिक्स सदस्यों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक मजबूत तर्क दिया और कहा कि इसके साथ मुद्रा जोखिमों और पारस्परिक बही-खाते के निपटान के प्रबंधन के तंत्र भी होने चाहिए।

पेजेशकियान ने कहा, “चूंकि वर्तमान वित्तीय प्रणाली सीमित संख्या में मुद्राओं पर केंद्रित होने के कारण राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील है,” इसलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक को निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए स्थानीय-मुद्रा ऋण और गारंटी के माध्यम से बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत बनना चाहिए।

ब्रिक्स घोषणापत्र ने व्यापार बाधाओं को निशाना बनाया

नई दिल्ली घोषणापत्र में एकतरफा टैरिफ और अन्य व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपार्यों पर भी चिंता जताई गई। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली “काफी समय से चौराहे पर खड़ी है” और चेतावनी दी कि व्यापार प्रतिबंधों के प्रसार से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

घोषणापत्र में कहा गया, “हम एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों में वृद्धि के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं जो व्यापार को विकृत करते हैं और डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के नियमों के असंगत हैं।” समूह ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे एकतरफा, दंडात्मक और भेदभावपूर्ण उपायों का भी विरोध किया और कहा कि वे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को असमान रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

ब्रिक्स ने विश्व व्यापार संगठन के सुधार के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की और डब्ल्यूटीओ को केंद्र में रखते हुए एक गैर-भेदभावपूर्ण, खुले, न्यायसंगत, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी, अनुमानित और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार



प्रणाली का आव्हान किया। इसने डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र को पूरी तरह से चालू स्थिति में तत्काल बहाल करने की भी वकालत की।

भारत की अध्यक्षता में आठ महीने का कार्य

दलेला ने कहा कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता के तहत आठ महीने के काम के बाद हुआ, जिसमें विषयगत समूहों, मंत्रिस्तरीय बैठकों, कार्य समूहों, व्यावसायिक सत्रों और अन्य पहलों के तहत 350 से अधिक बैठकें शामिल थीं। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में चल रहे संघर्षों और आर्थिक अनिश्चितताओं के प्रभाव को भी शामिल किया गया, जिसमें नेताओं ने संवाद, कूटनीति और मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व पर बल दिया।

भारत अपने 2026 के कार्यकाल के तहत नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण” (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) थीम के मार्गदर्शन में कर रहा है।

फिटनेस और स्वास्थ्य क्षेत्र से टैरो-न्यूमेरोलॉजी तक का सफर

कोविड में सीखी विद्या, आज दुनिया भर में बज रहा भोपाल की ‘द डिवाइन रुही’ का डंका
नई राह चुनकर पेश की महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल,
सटीक भविष्यवाणी से बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल भी रह गई थीं हैरान



भोपाल । प्रकाश त्रिपाठी । महिला सशक्तिकरण का असली अर्थ तब सार्थक होता है, जब एक महिला अपनी बनी-बनाई सुरक्षित राह से अलग हटकर कुछ नया करने का साहस जुटाए

और अपनी मेहनत से शिखर तक पहुंचे। राजधानी भोपाल की रुही राय की कहानी कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक है। कभी जिम और स्वास्थ्य (हेल्थ) सेक्टर में काम करने वाली रुही, आज दुनिया भर में ‘द डिवाइन रुही’ (The Divine Ruhii) के नाम से एक मशहूर टैरो कार्ड रीडर और न्यूमेरोलॉजिस्ट बन चुकी हैं।

एक महिला होकर जिस तरह उन्होंने अपने करियर की दिशा बदलकर यह मुकाम हासिल किया है, वह हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

कोविड के एकांत को बनाया ताकत, सीखी नई विद्यारुही का यह सफर बेहद दिलचस्प और साहसिक है। पहले वे जिम और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही थीं। लेकिन कोरोना महामारी (कोविड-19) के दौरान जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी, तब रुही ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस खाली समय को अपनी ताकत बनाया और घर बैठे टैरो कार्ड, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु और क्रिस्टल विद्या की विधिवत शिक्षा लेना शुरू किया।

किसी भी काम को आधे-अधूरे ज्ञान के साथ न करने की अपनी जिद के चलते, वे पहले इसमें पूरी तरह पारंगत हुईं और फिर इसे अपना नया प्रोफेशन बनाया। शहनाज गिल भी रह गईं थीं हैरान रुही की भविष्यवाणियों की सटीकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस शहनाज गिल के लिए किया गया उनका प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक बैठा था। खुद शहनाज भी उनकी इस विद्या से हैरान रह गईं थीं।

फिटनेस फील्ड के बाद बिल्कुल नए क्षेत्र में आकर इतनी जल्दी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हस्तियों और आम लोगों का भरोसा जीतना भोपाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

4000 से ज्यादा क्लाइंट्स और सम्मान की लंबी फेहरिस्त आज करियर में रुकावट, शादी में देरी, बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब एनालिसिस या धन आकर्षण (Money attraction) जैसी जीवन की हर उलझन का वे अचूक समाधान दे रही हैं।

उनके सटीक मार्गदर्शन के चलते दुनियाभर

से 4000 से ज्यादा क्लाइंट्स उनसे जुड़ चुके हैं और उन्हें गूगल पर शानदार 5-स्टार रेटिंग्स मिली हुई हैं। रुही की इस विशेषज्ञता को कई प्रतिष्ठित मंचों पर सराहा गया है। उन्हें ‘एम.पी. गौरव रत्न अवार्ड’, ‘मावे शाइन्स अवार्ड’ और ‘सिटी एक्सीलेंस अवार्ड’ जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है।

सरल संवाद और डिजिटल पहचान रुही की सबसे बड़ी खूबी उनकी आम बोलचाल वाली बेहद सरल संवाद शैली है, जिससे कोई भी इसान उनसे आसानी से कनेक्ट कर अपनी परेशानी साझा कर सकता है। वे अपनी वेबसाइट (www.thedivineruhii.in) और इंस्टाग्राम आईडी (@thedivineruhii) के जरिए डिजिटल दुनिया में भी लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं।

रुही राय की यह यात्रा सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह साबित करती है कि अगर एक महिला ठान ले और सही लगन से नई विद्या सीखे, तो वह किसी भी क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा सकती है।

भोपाल में ‘एस्ट्रो हीलिंग’ के विशेष मासिक सत्र शुरू, वैदिक ज्योतिष और वास्तु से मिलेगी तनावमुक्त जीवन की राह



भोपाल। राजधानीवासियों के जीवन में बढ़ती भागदौड़ और मानसिक तनाव के बीच ग्वालियर के प्रतिष्ठित संस्थान ‘एस्ट्रो हीलिंग यूनिवर्स’ ने भोपाल में अपनी सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। ज्योतिषाचार्य, वास्तु सलाहकार, रेकी हीलर और एनएलपी (NLP) प्रैक्टिशनर आचार्य श्री केपीएस चौहान के मार्गदर्शन में अब शहर में हर महीने एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को वैदिक ज्योतिष, महावास्तु और ऊर्जा चिकित्सा के जरिए उनकी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्याओं के सटीक और

व्यावहारिक समाधान उपलब्ध कराना है।

संस्थान का दृष्टिकोण जटिल कर्मकांडों के बजाय वैज्ञानिक और सहज उपायों पर आधारित है। यहां घर या कार्यस्थल की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए वास्तु, महावास्तु और एस्ट्रो-वास्तु का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा, ‘लाल किताब’ के “छोटे उपाय, बड़े परिवर्तन” वाले सिद्धांत को आम जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है।

इसमें आर्थिक परेशानियों के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाने, करियर की बाधाओं के लिए चावल-दूध का दान, गृह क्लेश के लिए सूर्य को अर्घ्य देने और नजर दोष जैसी रोजमर्रा की समस्याओं के बेहद आसान और अचूक उपाय शामिल हैं, जिन्हें कोई भी अपनी दिनचर्या में आसानी से अपना

सकता है। स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत परामर्श के साथ-साथ संस्थान डिजिटल माध्यमों पर भी सक्रिय है। देश-दुनिया के लोग वेबसाइट और इंस्टाग्राम (@astrohealinguniverse) के माध्यम से भी कुंडली विश्लेषण, करियर और विवाह संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं।

भोपाल में आयोजित होने वाले इन विशेष मासिक सत्रों में भीड़ से बचने और सुव्यवस्थित परामर्श के लिए व्यवस्था की गई है। शहरवासी हेल्पलाइन नंबर 9826437460 के माध्यम से पूर्व निर्धारित समय (अपॉइंटमेंट) लेकर इन सत्रों में शामिल हो सकते हैं।



स्टोर्स से बुक कर सकते हैं। यह अमेजन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल और क्रोमा जैसे ऑनलाइन रिटेलर्स पर भी उपलब्ध है। शुरुआती ऑफर्स के तहत चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक और नो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा भी दी जा रही है।

एक नज़र में आईफोन 18 प्रो सीरीज़ कीमत: प्रो (1.65 लाख रु.) | प्रो मैक्स (1.80 लाख रु.) प्रोसेसर: पावरफुल ए20 प्रो चिपसेट (A20 Pro Chip) कैमरा: डीएसएलआर जैसी ‘वेरिएबल अपरचर’ लेंस तकनीक नया AI अवतार: सिरि में चैटजीपीटी सपोर्ट, इन-ऐप एक्शन और स्क्रीन अवेयरनेस खास फीचर: हीटिंग रोकने के लिए एडवांस

आस्था, परंपरा और सेहत का “महापर्व तीज”

भोपाल । गलियों से लेकर आंगनों तक गुंजते सावन के सुमधुर लोकगीत, हाथों में रखी गहरी सतरंगी मेहंदी और सोलह श्रृंगार में सजी महिलाएं इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि हमारी सनातन संस्कृति आज भी कितनी समृद्ध और ऊर्जावान है। आज देशभर में तीज का त्योहार पूरे उत्सास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है।

हालांकि, बाहरी तौर पर यह केवल सुहागिनों के व्रत और श्रृंगार का दिन लग सकता है, लेकिन गहराई में उतरें तो यह पति-पत्नी के अटूट प्रेम, प्रकृति से जुड़ाव और शरीर को मिलेगी बनाने वाले एक शानदार वैज्ञानिक फॉर्मूले का महापर्व है।

सनातन महत्व: संकल्प, समर्पण और शिव-पार्वती के प्रेम की अमर कथा सनातन परंपराओं में तीज का सीधा संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के अलौकिक मिलन से है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने जीवनसाथी के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या और निर्जला व्रत किया था। उनके इसी अटल संकल्प और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आज ही के दिन उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था।

यही कारण है कि सदियों से सुहागिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख-शांति और पति की दीर्घायु के लिए यह कठिन व्रत रखती आ रही हैं। वहीं, कुंवारी कन्याएं भी शिव जैसे सुयोग्य और आदर्श जीवनसाथी की कामना के साथ पूरी श्रद्धा से इस उपवास को करती हैं।

विज्ञान की कसौटी पर तीज: व्रत और श्रृंगार के पीछे का ‘हेल्थ साइक्रेट’ हमारी सनातन परंपराओं की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे मानव कल्याण का गहरा वैज्ञानिक आधार छिपा है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और शोधकर्ताओं ने भी तीज से जुड़े नियमों के उन कार्यों पर मुहर लगाई है, जिन्हें हमारे पूर्वज सदियों पहले समझ चुके थे:

* बांडी का नैचुरल डिटॉक्सिफिकेशन (ऑटोफैगी): जब महिलाएं तीज पर निर्जला या फलाहारी उपवास रखती हैं, तो पाचन तंत्र को लंबे समय बाद एक ज़रूरी ब्रेक मिलता है। करीब 12 से 16 घंटे के उपवास के बाद शरीर ‘ऑटोफैगी’

(Autophagy) मोड़ में चला जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर अपनी ही पुरानी, मृत और खराब कोशिकाओं को नष्ट करके नई और स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण करता है। दिलचस्प बात यह है कि इसी ‘ऑटोफैगी’ की खोज के लिए वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

* इन्सुलिटी और ब्लड शुगर में सुधार: सही तरीके से किया गया उपवास शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है और अंदरूनी सूजन (Inflammation) को कम करता है।

इससे हृदय का स्वास्थ्य बेहतर होता है, रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) नियंत्रण में रहता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होता है।

* मेहंदी का ‘कूलिंग इफेक्ट’: तीज पर हाथों और पैरों में मेहंदी रचाने की परंपरा है। मानसून के इस मौसम में वातावरण में उमस और नमी के कारण कई तरह की बीमारियां और तनाव पनपते हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेहंदी की तासीर बेहद ठंडी होती है। इसे हथेलियों और तलवों की नसों पर लगाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और मानसिक तनाव, सिरदर्द व घबराहट जैसी समस्याएं दूर होती हैं। * हैप्पी हार्मोन्स’ का नैचुरल बूस्टर: सावन के महीने में सहैलियों के साथ मिलकर झूलें झूलना, सजने-संवरने की तैयारियां करना और सामूहिक रूप से लोकगीत गाना कोई साधारण गतिविधि नहीं है। यह महिलाओं के मस्तिष्क में ‘एंडोर्फिन’ और ‘डोपामाइन’ जैसे हैप्पी हार्मोन्स के स्त्राव को तेजी से बढ़ाता है। यह सामूहिक उत्सव रोजमर्रा की मानसिक थकान, तनाव और डिप्रेशन को पूरी तरह मिटाकर मन को एक नई ऊर्जा से भर देता है।

तीज का यह पावन पर्व केवल एक धार्मिक कर्मकांड भर नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने, वैवाहिक रिश्तों में मिठास घोलने और हमारी शारीरिक व मानसिक सेहत को एक नया ‘रीस्टार्ट बटन’ देने का एक बेहतरीन माध्यम है। यह त्योहार इस बात का सबसे सुंदर उदाहरण है कि कैसे हमारी सनातन आस्था और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही दिशा में कदम मिलाकर चलते हैं, जिनका अंतिम लक्ष्य मनुष्य को भीतर और बाहर, दोनों तरफ से समृद्ध बनाना है।

कंटेंट ही असली किंग

‘हनुमान अंश’ की सादगी ने जीता दिल, 500 करोड़ी ‘टॉक्सिक’ को 300 करोड़ का भारी नुकसान

देश दर्पण संवाद / प्रकाश त्रिपाठी । भोपाल

सिनेमा की दुनिया में यह एक बार फिर साबित हो गया है कि दर्शक सिर्फ कहानी के दीवाने होते हैं, ‘कंटेंट ही किंग होता है’। एक तरफ जहाँ ‘हनुमान अंश’ जैसी सादी और सिंपल कहानी वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार काम किया है, वहीं दूसरी तरफ 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश वाली यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ को करीब 300 से 350 करोड़ रुपये के भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यह तुलना साफ दर्शाती है कि दर्शकों को अब सिर्फ बड़े स्टार्स नहीं, बल्कि दमदार कहानी चाहिए। ‘टॉक्सिक’ से बॉक्स ऑफिस पर बड़ी उम्मीदें थीं और यश की ‘स्टार पावर’ के कारण पहले दिन इसे दुनियाभर में करीब 140 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग भी मिली थी। लेकिन दूसरे ही दिन फिल्म की कमाई बुरी तरह गिरकर करीब 37 करोड़ रुपये पर आ गई। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस असफलता की सबसे बड़ी वजह ‘टॉक्सिक’ के बेहद कमजोर कंटेंट और ढीली कहानी को बताया है।

खराब तरीके से बुनी गई इस फिल्म की कहानी अलग-अलग जगहों पर भटकती हुई महसूस होती है, जिससे दर्शक लगातार जुड़ नहीं पाते और बोरीयत महसूस करते हैं। यहाँ तक कि फिल्म का अंत भी ऐसा

था जिसे दर्शकों ने सिर से नकार दिया। ‘टॉक्सिक’ के इस कमजोर प्रदर्शन का सीधा फायदा ‘हनुमान अंश’ जैसी फिल्मों को मिला, जिन्हें सिनेमाघरों में ज्यादा स्क्रीन्स दी गईं।

‘हनुमान अंश’ की सफलता ने यह दिखा दिया कि अगर कहानी में दम हो, तो एक सिंपल फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार कर सकती है। वहीं, ‘टॉक्सिक’ का हथ्र बताता है कि स्टार पावर आपको अच्छी ओपनिंग तो दिला सकती है, लेकिन अगर फिल्म का निर्माण कमजोर हो और कहानी दर्शकों को बांधने में नाकाम रहे, तो फिल्म सिनेमाघरों में टिक नहीं सकती। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कोई भी स्टार पावर एक कमजोर कहानी की भरपाई नहीं कर सकती।

